

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I--खण्ड 1

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सर 102]

नई विल्ली, शनिवार, जून 25, 1977 ग्राबाढ़ 4, 1899

No. 102]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 25, 1977/ASADHA 4, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING (Revenue Wing)

RESOLUTION

New Delhi, the 25th June 1977

No. A-11019/70/77-Ad. VII.—The Government of India have decided to appoint a Committee of Experts to examine and suggest legal and administrative measures for simplification and rationalisation of the direct tax laws and such further alterations as are desirable in the interest of the national economy.

2. The Committee will consist of the following -

Chairman.

Shri N A Palkhivala Senior Advocate, Bombay. . .

Members

Shri C C Chokshi, Chartered Accountant, Bombay.

Shri Harnam Shankar former President, Income-tax Appellate Tribunal, New Delhi.

Shri C C Ganapathi, Chairman, Settlement Commission, New Delhi.

Secretary

Shri T S. R. Narasimhan Commissioner of Income-tax, Bombay.

3 The Comm e will-

(a) recommend measures to simplify and rationalise the laws relating to income-tax, surtax, wealth-tax, gift-tax and estate duty, and to alter those laws with a view to making them readily comprehensible to taxpayers, reducing litigation and thus subserving the interest of the national economy;

- (b) suggest ways and means of improving the administration of those laws and expediting assessment, appellate and other proceedings under those laws.
- (c) examine the advisability of consolidating the four laws relating to incometax, surtax, wealth-tax and gift-tax into one Act;
- (d) prepare drafts of the Bills for being presented before Parliament.
- 4. The headquarters of the Committee will be at Bombay The Committee will devise its own procedure, and may call for such information as it considers necessary.
- 5. The Department of Revenue and Banking will provide the secretariat of the Committee.
- 6 The Committee will submit its Report and the draft Bills to the Ministry of Finance by 31st December, 1977

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information

राजस्य धीर बेंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

संकल्प

नई दिल्ली, 25 जून, 1977

सं॰ ए-11019/70/77-प्रशा VII.—प्रत्यक्षकर कानूनो का सरलीकरण करने श्रौर उन्हें युक्तिसंगत बनाने तथा उनमें राष्ट्रीय श्रर्थव्यवस्था है हित श्राय में बाछनीय पर्विनंन करने की दृष्टि से उनकी जांच करने श्रौर उनके सबध में कानूनी तथा प्रणामनिक उपाय मुझाने के लिए भारत सरकार ने एक विशेषक्ष समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है।

2. समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा ---

ग्रह्यक्ष

श्री एन०ए० पालकीवाला, वरिष्ठ एडवोकेट, बम्बई ।

सबस्यगण

श्री सी०सी० चौश्री, चार्टर्ड एकाउन्टेट, बम्बई ।

श्री हरनाम शकर, भूतपूर्व प्रध्यक्ष, श्रायकर श्रपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली ।

श्री सी० सी० गणपति, श्रध्यक्ष, समझौता श्रायोग, नई दिल्ली ।

सचिव

श्री टी०एस०ग्रार० नरिसम्हन्, ग्रायकर ग्रायुक्त, बम्बई ।

- 3. समिति निम्नलिखित कार्य करेगी---
 - (क) सिमिति श्रायकर, श्रितिकर, धनकर, दानकार और सम्पदाणुल्क से सबिधत कानूनों का सरलीकरण करने तथा उनको युक्तिसगत बनाने के, श्रीर इन करो से संबंधित कानूनों में इस दृष्टि से परिवर्तन करने के लिये कि वे करदाताश्रों के लिए सहज ही बोधगम्य बन सके, उपायों की सिफारिश करेगी ताकि मुकदमें बाजी कम हो श्रीर राष्ट्रीय श्रर्थव्यवस्था का हित साधन हो सके;

- (ख) समिति उक्त कानूनो के प्रणासन में सुधार करने तथा उन कानूनो े ग्रन्तर्गत किये जा रहे कर-निर्धारण, ग्रपीलीय तथा श्रन्य कार्यवाहियों को णीधता से करने के लिए उपाय सुझायेगी ;
- (ग) मिमिति ग्रायकर, भ्रतिकर, धनकर ताः दानकर से साधित चार कानूनो को एक श्रिधिनयम में समेकित करने के ग्रीचित्य की जाच करेगी ,
- (घ) समद में पेण करने के लिये विधेयको के प्रारूप नैयार करेगी।
- 4 मिमिति का मुख्यालय बग्बई भें होगा। मिमिति श्रपनी कार्यविधि निर्धारित करेगी श्रीर जो सूचना वह श्रावश्यक समझेगी मगवायेगी।
 - 5. राजस्य ग्रीर बैकिंग विभाग, समिति के सचिवालय की व्यवस्था करेगा।
- 6. समिति ग्रपनी रिपोर्ट ग्रीर विधेयको के प्रारूप 31 दिसम्बर, 1977 तक, वित्त मक्षालय को प्रस्तुत करेगी ।

ग्रावेश

श्रादेण दिया जाता है कि इस सकल्प की प्रति सभी सबिधत व्यक्तियों को भेजी जाय श्रीर इसे सर्वसाधारण की सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाणित किया जाय।

हिमाद्रि नारायण राय, सचिव ।